

प्रेषक,

मनीषा पंवार,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-01.

देहरादून, 3 जनवरी 2009.

विषय : अनुसूचित जनजाति राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खटीमा, ऊधमसिंह नगर में फिटर कार्यशाला, स्टोर एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-268/XVII(1)-01/2008-11(20)/2004, दिनांक 18 मार्च 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनुसूचित जनजाति राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खटीमा, ऊधमसिंह नगर में फिटर कार्यशाला, स्टोर एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु अवशेष रूपये 22,30,000/- (रूपये बाईस लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. शासनादेश संख्या-267/XXVII/2008, दिनांक 27 मार्च 2008 के प्रस्तर-19 के अनुसार स्वीकृत कार्य, आगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृति, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति इत्यादि का विवरण संलग्न प्रपत्र-1 से 4 पर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें "शिड्यूल ऑफ रेट" में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितने कि स्वीकृत मानक हैं, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग और "MORTH" द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।
7. आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उन्हीं मदों पर किया जाए। एक मद की धनराशि दूसरी मदों में कदापि व्यय न की जाए।
8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में परीक्षण करा लिया जाए तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।
9. कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए उक्त कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराकर हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित कराया जाएगा। उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किए जाएंगे।

विलम्ब के कारण यदि आगणन का पुनरीक्षण किया जाता है तो उसे अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे। स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।

10. स्वीकृत धनराशि का व्यय बजट मैन्युअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
11. कार्य कराते समय निविदा विषयक नियमों एवं मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।
12. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
13. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए तथा कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा।
14. शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
16. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय की "अनुदान संख्या-31" के "आयोजनागत पक्ष" के लेखाशीर्षक "4225-अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-277-शिक्षा-04-अनुसूचित जनजाति आई.टी.आई. में निर्माण कार्य" के मानक मद "24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे खाला जाएगा।
17. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-634(P)/XXVII-3/2008-09, दिनांक 13 जनवरी 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)  
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 105 (1)/XVII-1/2008-11(20)/2004, तददिनांक :  
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
9. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पत्रिका।

आज्ञा से,

(सी.एम.एस. विष्ट)  
अमर